

लोको पायलटों का संघर्ष जिंदाबाद !

कामगार एकता कमिटी का बयान, 22 सितम्बर 2024

लोको पायलट साथियों,

आपका संगठन AILRSA के नेतृत्व में, पूरे देशभर आपने अपनी कई महत्वपूर्ण मांगों के लिए संघर्ष छेड़ा है। हमेशा की तरह, हम कामगार एकता कमिटी की ओर से आपके संघर्ष का पुरजोर समर्थन करते हैं।

- 1) रेलवे का निजीकरण एवं निगमीकरण बंद किया जाये,
- 2) रनिंग स्टाफ को आवधिक विश्राम 46 घंटे दिया जाये, लगातार दो रात्रि से अधिक रात्रि ड्यूटी ना कराई जाये, तथा रनिंग स्टाफ को ३६ घंटे में मुख्यालय वापिस किया जाये,
- ३) मालगाड़ी में अधिकतम 8 घंटे तथा सवारी गाडी में अधिकतम 6 घंटे ड्यूटी निर्धारित की जाये,
- ४) रनिंग स्टाफ के सभी रिक्त पद तुरंत स्थाई तौर पर भर दिए जायें.

इन प्रमुख मांगों के अलावा वेतन तथा प्रोमोशन, टॉयलेट का इंतजाम, महिला लोको पायलटों के लिए विशेष प्रबंध, आदि से संबंधित भी कई मांगें हैं।

कामगार एकता कमिटी का मानना है कि लोको पायलट, स्टेशन मास्टर्स, गार्ड, सिग्नल एंड टेलीकोम, ट्रेक मेंटेनर, आदि रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित सभी कर्मचारियों पर एक विशेष जिम्मेदारी है, "हर रोज कुछ करोड़ यात्रियों की एवं दसियों लाख टन चीज वस्तुओं की समयोचित तथा सुरक्षित यातायात"। आप सभी पुरजोर प्रयास करके वह जिम्मेदारी निभाने की हमेशा ही पूरी कोशिश करते हैं। मगर रेल प्रशासन का आपके साथ बेहद लापरवाही का रवैया रहा है। उस वजह से आपको कार्यस्थल पर भारी तनाव का मुकाबला करना पड़ता है जिसका बेहद विपरीत असर आपके स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन पर होता है। तनाव की हालातों में काम करने से आपकी एवं यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में आती है। इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई रेल दुर्घटना होती है तो बड़े बेशर्मी से रेल प्रशासन और सरकार आप ही को दोषी के कंधे में खड़े करते हैं। **कामगार एकता कमिटी का मानना है कि आपको तनावरहित और सम्मानजनक हालातों में काम करना चाहिए और वह पूरी तरह रेल प्रशासन एवं सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।**

साथियों,

हम आपको सलाम करते हैं क्योंकि बेहद मुश्किलों एवं रेल प्रशासन एवं सरकार के जबरदस्त दबाव के बावजूद आपने आपका संघर्ष अधिक व्यापक एवं तीखा किया है। उस संघर्ष की वजह से सरकार को झुकना पड़ रहा है। यही कारण है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सरकार को पत्र लिखकर रेलवे में पोस्ट भरने की बात उठानी पड़ी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अलग अलग झोन में उच्च अधिकारी पत्र लिखकर निर्देश दे रहे हैं कि 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लोको पायलट को ना दी जाये, आदि। मगर यह सब एक नाटक या नौटंकी प्रतीत होता है क्योंकि वास्तव में अगर लोको पायलट ज्यादा ड्यूटी करने से इंकार करते हैं तो उनपर झूठे आरोप लगाकर सस्पेंड करना, ट्रांसफर करना, ऐसी कार्यवाही अधिकारी करते हैं। पूना डिविजन में आपका यही अनुभव रहा है। **रेल प्रशासन एवं सरकार की इस कूटनीति की हम कामगार एकता कमिटी की ओर से भर्त्सना करते हैं।** पूना डिविजन में आपने मजबूत एकता से उस कार्यवाही का विरोध किया एवं अधिकारियों को वह अन्यायपूर्ण कार्यवाही खारिज करनी पड़ी। आपके मजबूत एकता की हम सराहना करते हैं।

साथियों,

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों का निजीकरण करने की सरकार की कोशिशों की वजह से सभी उद्योगों में बड़ी तादाद में रिक्तियाँ हैं, काम के हालात बेहद असुरक्षित हो गए हैं, नौकरी की असुरक्षा बेहद बढ़ गई है, जिससे सभी मजदूरों को बेहद बुरा असर झेलना पड़ रहा है। कामगार एकता कमिटी का मानना है कि निजीकरण की यह नीति केवल मजदूर विरोधी ही नहीं, बल्कि समाजविरोधी एवं देशविरोधी है। इसीलिए, कामगार एकता कमिटी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मजदूरों एवं उपभोक्ताओं, याने की आम जनता की एकजुट बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। निजीकरण विरोधी सर्व हिंद फोरम (AIFAP) के कार्य को देशभर फैलाना उसी काम में एक कदम है। उस माध्यम से आपके संघर्ष को भी हमने लोकप्रिय बनाया है।

आइए साथियों, हम मिलकर आपके इस जायज संघर्ष को आम जनता का समर्थन प्राप्त करने की दिशा में अभियान चलाएं!

आइए साथियों, हम मिलकर देश के दूसरे मजदूरों से आपकी एकता को और मजबूत बनाएं!